एक प्रभावी टीकाकरण वितरण नीति की ओर

-लेखक - भास्कर दत्ता (प्रोफेसर, अर्थशास्त्र, अशोक विश्वविद्यालय)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (स्वास्थ्य) से संबंधित है।

द हिन्दू

28 दिसम्बर, 2020

सरकार को ट्राइएज स्कीम में निहित सिद्धांत की जांच करनी चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि क्या निजी खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया जाये या नहीं?

भारत अगले 6-7 महीनों में COVID-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए 300 मिलियन लोगों का टीकाकरण करने की योजना बना रहा है। सरकार की योजना स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य अग्रिम पंक्ति के श्रमिकों को प्राथमिकता देने की है, इसके बाद 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का टीकाकरण किया जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि जुलाई या अगस्त 2021 तक लगभग 20% आबादी को टीका लगाया जाएगा।

यहाँ कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करना आवश्यक है। शायद सबसे महत्वपूर्ण सरकार द्वारा अपनाई गई ट्राइएज स्कीम (सबसे अधिक जरूरतमंद मरीज को पहले तरजीह देना) का सिद्धांत है। एक अलग और कुछ हद तक विवादास्पद मुद्दा यह है कि क्या सरकार निजी खिलाड़ियों को टीकाकरण प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर शामिल होने की अनुमति देगी।

किसे मिलेगी प्राथमिकता?

फ्रंट-लाइन कार्यकर्ताओं और बुजुर्गों को प्राथमिकता देने की सरकार की रणनीति, U.K. और U.S. में पालन किये जाने वाले अभ्यास के अनुरूप है। इसके लिए तर्क यह दिया गया है कि भविष्य में संक्रमित होने वाले लोगों के साथ-साथ उन लोगों की भी रक्षा की जाए जो संक्रमण के लिए सबसे अधिक असुरक्षित हैं। हालांकि, इस तरह के एक टीकाकरण अभियान का दो अलग-अलग उद्देश्य होना चाहिए, जिसमें पहला है, टीकाकरण करने वालों को सुरक्षा प्रदान करना और दूसरा है, वायरल ट्रांसमिशन की गति और प्रसार को कम करना। आदर्श रूप से, एक टीका वितरण कार्यक्रम को इन दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए।

कुछ मामलों में, इन दो उद्देश्यों के बीच कोई संघर्ष नहीं है। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए दी गई प्राथमिकता दोनों उद्देश्यों को पूरा करती है- ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उच्च स्तर के जोखिम से घिरे होते हैं और वे सक्रिय रोग वैक्टर के रूप में भी कार्य करते हैं क्योंकि वे बड़ी संख्या में लोगों के संपर्क में रहते हैं। हालाँकि, वृद्ध लोगों को दी गई प्राथमिकता वास्तव में लंबे समय के लिए वायरस द्वारा प्रदत्त कुल सामाजिक और आर्थिक लागत को कम नहीं कर सकती है। वृद्ध लोगों का मूवमेंट या आवागमन कम होता है, साथ ही सामाजिक स्तर पर ये कम सक्रिय रहते हैं, इसलिए उनमें वायरस फैलने की संभावना कम होती है। जाहिर है, एक कम उम्र का व्यक्ति जो बड़ी संख्या में लोगों के संपर्क में रहता है, खुद भी संक्रमित हो सकता है और बाद में दूसरों को भी संक्रमित कर सकता है। इससे पता चलता है कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों - उदाहरण के लिए, धारावी स्लम - को वर्तमान रणनीति के तहत जितना संभव हो सके, उससे अधिक ध्यान देना चाहिए।

निजी अस्पतालों को शामिल करना

सरकार की खरीद की रणनीति पूरी तरह से घरेलू स्रोतों पर निर्भर करती है। सरकार की यह भी योजना है कि वह निजी अस्पतालों को शामिल किए बिना वितरण के लिए पूरी तरह से सार्वजनिक संसाधनों पर भरोसा करे। इसके अलावा, सरकार

टीकाकरण की पूरी लागत वहन करने की योजना बना रही है। उत्तरार्द्ध विशेष रूप से महत्वपूर्ण और उचित है क्योंकि महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। लेकिन निम्नलिखित प्रस्ताव पर हमें विचार करना चाहिए। मान लीजिए कि फाइजर या किसी अन्य बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी ने वैक्सीन को अधिकृत करने के साथ-साथ आयात करने और इसे खरीदने वालों (लाभ के लिए) को बेचने की अनुमति देने के लिए सरकार से संपर्क किया है, यहाँ सरकार को क्या करना चाहिए?

सरकार का कोई भी अनुमोदन संपन्न व्यक्ति को टीकाकरण कतार में सबसे आगे ला खड़ा करेगा। सरकार पर यह भी आरोप लगने लगेंगे कि सरकार जनसंख्या में समृद्ध समूहों के हितों पर अधिक ध्यान दे रही है। लेकिन शायद एक अधिक विवादास्पद विश्लेषण यह सुझाव देगा कि निजी क्षेत्र को वैक्सीन की अतिरिक्त आपूर्ति प्रदान करने की अनुमति देना वास्तव में एक खराब नीतिगत निर्णय नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण विचार जो ध्यान में रखा जाना है, वह यह है कि इससे गरीबों को वैक्सीन की उपलब्धता में कमी नहीं होगी। सरकार को घरेलू स्तर पर उपलब्ध सभी टीकों की खरीद जारी रखनी चाहिए और उन्हें अपने वितरण चैनल के माध्यम से आपूर्ति करनी चाहिए।

यह सुनिश्चित करना है कि गरीबों के लिए वैक्सीन की उपलब्धता में कोई कमी न हो। वास्तव में, आपूर्ति में वृद्धि हो सकती है और इसलिए कम संपन्न लोगों को कम प्रतीक्षा करनी पड़ेगी क्योंकि लक्ष्य समूह के कुछ अमीर व्यक्ति सरकारी वितरण प्रणाली से बाहर निकल जाएंगे और कुछ निजी आउटलेट पर टीकाकरण करना पसंद करेंगे।

पूरी आबादी के लिए एक और संभावित लाभ यह है कि जितने अधिक टीके लगेंगे, उतना ही कम गैर-टीकाकरण आबादी के बीच वायरस संचरण की गति होगी।

लेकिन क्या इसकी संभावना है कि निजी आपूर्तिकर्ता भारत में वैक्सीन के आयात और वितरण के लिए सरकार की अनुमति का अनुरोध करेंगे? दो हालिया घटनाक्रम यह बताता है कि यह संभव है। पहली खबर यह है कि नियामक अधिकारियों ने अमेरिका भर में मॉडर्न वैक्सीन (Moderna vaccine) के आपातकालीन उपयोग को अधिकृत किया है। कई अन्य टीके पहले से ही चरण 3 परीक्षणों का आयोजन कर रहे हैं और इस बात की प्रबल संभावना है कि COVID-19 के टीके की वैश्विक आपूर्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। दूसरा यह है कि बेल्जियम के एक मंत्री ने कीमतों के बारे में बहुत संवेदनशील जानकारी ट्वीट की है जो यह खुलासा करता है कि यूरोपीय संघ ने COVID-19 टीकों के लिए भुगतान करने पर अपनी सहमति किस मीमत पर की है।

इस ट्वीट से यह पता चलता है कि ये कीमतें उन कीमतों की तुलना में काफी कम हैं, जो कि मॉडर्न और फाइजर (Pfizer), अन्य देशों को पेश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर, ट्वीट से पता चलता है कि मॉडर्न 18 डॉलर प्रति डोज के हिसाब से चार्ज कर रहा है जबकि फाइजर की कीमत 12 यूरो से भी कम है। इसके विपरीत, भारतीय समाचार पत्रों ने उल्लेख किया है कि फाइजर भारत में 37 डॉलर प्रति डोज की कीमत पर विचार कर रहा है। बेशक, यूरोपीय संघ को एक बहुत अच्छा सौदा मिल सकता है, क्योंकि इसके बाजार का बड़ा आकार इसे सौदेबाजी की अपार शक्ति देता है। लेकिन अगर टीकाकरण की कीमत 5,000 रूपए के आसपास रहती है तो भारत भी एक बड़ा बाजार सिद्ध हो सकता है।

Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. मॉडर्न वैक्सीन (Moderna vaccine) न्यूमोनिया का टीका है, जिसे भारतीय दवा कंपनी सीरम द्वारा विकसित किया गया है।
2. वैश्विक स्तर पर COVID-19 वैक्सीन की मानक मूल्य 5,000 रूपए तय की गयी है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 2 **(b)** केवल 1
(c) 1 और 2 दोनों **(d)** न तो 1, न ही 2

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements:-

1. Moderna vaccine is a pneumonia vaccine, developed by the Indian Claims Company Serum.
2. The standard price of COVID-19 vaccine globally has been fixed at Rs.5,000.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 2 **(b)** Only 1
(c) Both 1 and 2 **(d)** Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. COVID-19 टीकों के वितरण में व्याप्त चुनौतियों की चर्चा करते हुए बताएं क्या खुले बाजार की शक्तियों को वैक्सीन की लागत और पर्याप्तता निर्धारित करनी चाहिए? (250 शब्द)

Q. While discussing the challenges faced in the distribution of COVID-19 vaccines, explain should the open market forces determine the cost and adequacy of the vaccine?
(250 Words)

World
Committed To Excellence

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।